भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4314

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

05चैत्र, 1947 (शक)

तमिलनाडु में 'पीएमजीदिशा'

4314.डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) केन्द्रों की ग्रामवार संख्या कितनी है;

(ख) 'पीएमजीदिशा' के तहत कितने डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं तथा कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से इन केंद्रों पर नियमित प्रशिक्षण को सुचारू रूप से पुनः आरंभ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय तथा तमिलनाडु दोनों स्तरों पर 'पीएमजीदिशा' योजना के प्रमाणित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर या कौशल-आधारित लाभ कौन से हैं; और

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता तथा रोजगार सृजन पर 'पीएमजीदिशा' के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क):प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) की शुरुआत तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता पहुंचाने के लिए की गई थी। योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ। यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा देश भर में 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में फैले 4.39 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की गई।6 करोड़ के सापेक्ष, देश भर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। देश भर में समान भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसलिए, लक्ष्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित किए गए तथा उनकी निगरानी गांव स्तर पर नहीं अपितुग्राम पंचायत स्तर पर ही की गई।

(ख):कोविड-19 महामारी के दौरान भी यह योजना क्रमबद्ध तरीके से जारी रही, जबकि संबंधित केंद्रीय/राज्य/जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों में दी गई छूट का पालन किया गया। पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सभी प्रशिक्षण केंद्रों/सीएससी में उद्देश्यों के अनुरूप बनाए रखा गया:

- सभी प्रशिक्षण केंद्रों/सीएससी में सभी अभ्यर्थियों के लिए मल्टीमॉडल प्रारूप में 22 भाषाओं में मानकीकृत मल्टीमीडिया सामग्री के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया;
- कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) बनाई गईं और प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए सभी प्रशिक्षण केंद्रों के साथ साझा की गईं;

- प्रशिक्षण केंद्रों को अपनी गतिविधियां पुनः आरंभ करने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके साथ वर्चुअल सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गईं;
- पंजीकृत/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो प्रशिक्षण और/या प्रमाणन के लिए उपस्थित होने में असमर्थ थे;
- पीएमजीदिशा पोर्टल पर बुनियादी सूचना के साथ एक चैटबॉट बनाया गया था जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था;
- प्रशिक्षण केंद्रों को लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर समूहों में शामिल होने और इन समूहों के माध्यम से प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया;
- पीएमजीदिशा की विषय-वस्तु को डिजीशाला चैनल पर अपलोड किया गया, ताकि अभ्यर्थी स्वयं इसका संदर्भ ले सकें और मामूली प्रशिक्षण/संशोधन के बाद पंजीकरण और मूल्यांकन के लिए तैयार हो सकें।

(ग) और **(घ):**राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें राउंड (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) आयोजित किया। सर्वेक्षण के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 78.4 प्रतिशत ने 'संदेश (जैसे, ई-मेल, मैसेजिंग सेवा, एसएमएस) को संलग्न फाइलों (जैसे, दस्तावेज, चित्र, वीडियो) के साथ भेजने' के कौशल के निष्पादन की सूचना दी।इसके अलावा, लगभग 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और लगभग 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन और/या मोबाइल फोन है। उक्त रिपोर्ट से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट-फोन के उपयोग, इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया और योजना को 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया गया है ।

इसके अलावा, पीएमजीदिशा योजना का प्रभाव विश्लेषण तीन एजेंसियों अर्थात् आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। पीएमजीदिशा योजना का नवीनतम प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आईआईपीए द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का सार यह है कि पीएमजीदिशा अपने बड़े पैमाने और दूर से संचालित परीक्षाओं के उपयोग के कारण एक अनूठी योजना है। पीएमजीदिशा के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने अपने प्रतिभागियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचनाओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुँच को सक्षम करके लाभान्वित किया है, जिससे देश में समग्र डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) में 18%, जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए 12% और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए 11% निधि का उपयोग करके कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया है।
- महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है और ग्रामीण स्तर पर उनके समावेश से पूरे परिवार के लिए सीखने का रास्ता खुलेगा।
- 55% से अधिक उत्तरदाताओं ने पीएमजीदिशा प्रशिक्षण के बाद अपनी आजीविका में प्रत्यक्ष लाभ होने का हवाला दिया।
- लगभग 50% उत्तरदाताओं ने कहा कि पीएमजीदिशा ने उन्हें बेहतर नौकरी पाने में मदद की।

******